



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 1972/कार्तिक 27, 1894

No. 255]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1972/KARTIKA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सहायी दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th November 1972

SUBJECT.—Procurement of imported materials by actual users through Steel Bank.

No. 165-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 2 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 126-ITC(PN)/72 dated the 26th August, 1972 in terms of which the stocks of approved categories of steel maintained in the Steel Bank would be used for meeting the requirements of priority units off-the-shelf against valid import licence/release orders held by them or against foreign exchange allocations made by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) for release of steel material from the Steel Bank to project authorities.

2. In this connection, it is clarified that the facilities of the Steel Bank can be availed of by project authorities whose demands are of priority nature certified as such by the administrative ministries/sponsoring authorities and where requirements cannot wait for normal import procedures. The expression "priority units", referred to above, does not refer to "Priority Industries", as listed in Appendix I in the Import Trade Control Policy (Red Book, Vol. I) for April, 1972—March, 1973 but to projects deemed to be of importance. The objective of the scheme is to help reduce delays in matching priority demands with actual availability in terms of time in the execution of major projects and also in the fabrication of machinery and equipment for such projects, etc.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1972

विषय—वास्तविक उपयोगिताओं द्वारा इस्पात बैंक के माध्यम से आयातित वास्तुओं की अधिप्राप्ति ।

सख्या 165-आई० टी० सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सख्या : 126-आई/टी सी (पीएन)/72, दिनांक 26 अगस्त, 1972 के पैरा 2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार इस्पात बैंक से रखे गए इस्पात की अनुमोदित श्रेणियों का स्टॉक का उपयोग प्राथमिक एकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बैंड आयात लाइसेंस रिहाई आदेश के आधार पर या इस्पात बैंक से इस्पात की रिहाई के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा किए गए नियतन के आधार पर शेन्फ से किया जाएगा ।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस्पात बैंक की सुविधायें उन्ही परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध की जा सकती हैं जिनकी मांगें प्राथमिक किस्म की हैं और प्रशासनिक मंत्रालयों/प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा वे प्राथमिक प्रमाणित की गई हैं और जिस मामले में ये आवश्यकताये समान्य आयात क्रियाविधियों की प्रतीक्षा नहीं कर सकती । ऊपर उल्लिखित अभियुक्ति "प्राथमिक एकाओं" अप्रैल, 1972—मार्च, 1972 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के परिशिष्ट 1 में यथा सूचीबद्ध "प्राथमिक उद्योगों" को निर्दिष्ट नहीं करती, परन्तु महत्वपूर्ण समझी जाने वाली परियोजनाओं को निर्दिष्ट करती है । योजना का उद्देश्य मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समय के अनुसार वास्तविक उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक मांगों को पूरा करने में विलम्ब को कम करना है और ऐसी परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपस्कर का निर्माण करना आदि भी है ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।